RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 31.7.2025
Page No. 6, Size:(28.53)cms X (30.36)cms.

संवेदनहीनता की पराकाष्ठा

सीवर में मौत | पंकज चतुर्वेदी

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सोशल ऑडिट की ताजा रिपोर्ट से बेहद दर्दनाक सच्चाई सामने आई है कि सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले 90% से ज्यादा मजदूरों के पास किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण नहीं थे। जांचकर्ताओं ने 2022-23 के बीच 8 राज्यों के 17 जिलों में हुई में हुई 54 मौतों की गहराई से पड़ताल की। पाया कि 54 मौतों में से 49 मामलों में मजदूरों ने कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं पहना था। पांच मामलों में उनके पास दस्ताने थे और सिर्फ एक मामले में दस्ताने और गमबूट, दोनों थे।

इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि 47 मामलों में मजदूरों को सफाई के लिए कोई भी मशीनी उपकरण नहीं दिया गया था। यही नहीं, 27 मामलों में तो मजदूरों से काम के लिए सहमति तक नहीं ली गई थी और जिन 18 मामलों में लिखित सहमति ली भी गई, वहां उन्हें काम में शामिल जान के खतरों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सरकार ने संसद में स्वीकार किया कि 'नमस्ते' योजना के तहत 'खतरनाक तरीके से सीवर की सफाई' की समस्या के निराकरण पर काम करना बचा है। नमस्ते योजना के तहत अब तक देश भर में 84,902 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहचान की गई है, जिनमें से आधे से कुछ ज्यादा को ही पीपीई किट और सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं।

विदित हो कोई पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि सीवर की सफाई के दौरान श्रमिक मारे जाते हैं, तो उनके परिवार को सरकारी अधिकारियों को 30 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने साथ ही कहा था कि सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये और अन्य किसी विकलांगता से ग्रस्त होने पर 10 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। यह आदेश भी क्रियान्वयन के धरातल पर उतर नहीं पाया क्योंकि सीवर की सफाई करने वालों में से अधिकांश को कार्य सौंपने का कोई दस्तावेज ही नहीं होता।

सीवर के मौतघर बनने का कारण सीवर की जहरीली गैस बताया जाता है। हर बार कहा जाता है कि यह लापरवाही

का मामला है। पुलिस ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेती है। शायद यह पुलिस को भी नहीं मालूम है कि इस तरह सीवर सफाई का ठेका देना हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मुंबई हाई कोर्ट ने 12 साल पहले सीवर की सफाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। सरकार ने भी 2008 में अध्यादेश ला कर गहरे सीवर में सफाई का काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की अनिवार्यता की बात कही थी। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश मामलों में मजदूरों को काम पर लगाने का कोई रिकार्ड ही नहीं होता। सिद्ध करना मुश्किल होता है कि अमुक को अमुक ने इस काम के लिए बुलाया था या काम सौंपा था। अनुमान है कि हर साल देश भर के सीवरों में औसतन एक हजार लोग दम घुटने से मरते हैं। जो दम घुटने से बच जाते हैं, उनका जीवन सीवर की विषैली गंदगी के कारण नरक से भी बदतर हो जाता है। देश में दो लाख से अधिक लोग जाम सीवरों को खोलने, मेनहोल में घुस कर जमा गाद, पत्थर हटाने के काम में लगे हैं। महीनों से बंद पड़े इन नरक कुंडों में कार्बन मोनो आक्साइड, हाईड्रोजन सल्फाइड, मीथेन जैसी दमघोटू गैसें होती हैं।

यह शर्मनाक पहलू यह है कि जानते हुए भी कि भीतर जानलेवा गैस और रसायन हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को बगैर सुरक्षा-साधनों के भीतर ढकेल देता है। सीवरों में घरेलू निस्तार ही नहीं होता, उनमें कारखानों की गंदगी भी होती है। आज घर भी विभिन्न रसायनों के प्रयोग स्थल बन चुके हैं। इनसे निकसित पानी में ग्रीस-चिकनाई, क्लोराइड और सल्फेट, पारा, सीसा के यौगिक, अमोनिया गैस और न जाने क्या-क्या होता है। सीवरेज के पानी के संपर्क में आने पर सफाईकर्मी के शरीर पर छाले या घाव पड़ना आम है। नाइट्रेट और नाइट्राइड के कारण दमा और फेफड़े के संक्रमण होने की प्रबल आशंका होती है। सीवर के भीतर का अधिक तापमान इन घातक प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है। बदबू, गंदगी और रोजगार की अनिश्चितता में जीने वाले इन लोगों का शराब व अन्य नशों की गिरफ्त में आना लाजिमी है, जो गंभीर बीमारियों को खुला न्योता है।

वैसे कानून है कि सीवर सफाई करने वालों को गैस -टेस्टर (जहरीली गैस की जांच का उपकरण), गंदी हवा बाहर फेंकने के लिए ब्लोअर, टॉर्च, दस्ताने, चश्मा, कान ढंकने का कैप, हैलमेट मुहैया करवाना आवश्यक है। मुंबई हाई कोर्ट का निर्देश था कि सीवर की सफाई का काम ठेकेदारों के माध्यम से कतई नहीं करवाना चाहिए। काश! कानून इतनी कड़ाई से लागू हों कि मुआवजा देने की नौबत आए ही नहीं व सफाई कार्य से पहले ही जिम्मेदार एजेंसियां सुरक्षा उपकरण और कानून के प्रति संवेदनशील हों।

The News Minutes

NHRC seeks report on deaths due to food poisoning in Telangana Gurukul schools

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report within four weeks on the death of around 48 students and 886 incidents of food poisoning in Gurukul (residential) schools in Telangana

https://www.thenewsminute.com/telangana/nhrc-seeks-report-on-deaths-due-to-food-poisoning-in-telangana-gurukul-schools

Written by: IANS Published on: 30 Jul 2025, 9:37 am

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report within four weeks on the death of around 48 students and 886 incidents of food poisoning in Gurukul (residential) schools in Telangana

Secretaries of five societies, running the residential schools for students from Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Minorities, have been directed to submit the report.

This was one of 109 cases of human rights violations in Telangana heard by the NHRC during its two-day 'Open hearing and Camp Sitting', which concluded here on Tuesday.

NHRC Chairperson, Justice Shri V. Ramasubramanian, Members, Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi and Vijaya Bharathi Sayani heard the cases in the presence of the victims, complainants and the authorities.

In a case regarding the increasing stray dog menace, which was presented by a 5th standard student, the Commission directed the concerned authorities to come up with an SOP to curb the menace.

Out of Rs. 49.65 lakh recommended by the Commission in nine cases, Rs. 22.50 lakh was paid by the Telangana government, with the assurance to pay the remaining amount of Rs. 27.15 lakh.

In an incident involving the death of four persons in a blast at a DRDO-linked rocket propellant unit, three out of four families have been paid Rs. 50 lakh as relief, and the Commission has ordered payment of relief to the remaining victim's family.

In a case of wrongful arrest and lathi charge by the police, the NHRC directed the state government to submit all relevant documents, including environmental clearance and consent to establish the plant.

In a case regarding the trafficking of tribal women, the erring constable has been dismissed from the service, and many trafficked tribal women have been rescued.

The Commission on Tuesday held a meeting with the Chief Secretary, Director General of Police and other senior officers of the Telangana government on various aspects of

human rights. They were sensitised on the implementation of policies and programmes of the government in such a manner that no one is left out.

Emphasis was laid on preventive and systemic steps to be taken so that human rights are not violated. It was underscored that human rights concerns impacted by the environment, climate change, and business needed to be addressed.

Issues like crime against women, crime against children, man-animal conflict leading to deaths in many districts of Telangana, large number of children suffering from malnutrition, problems faced by the SC Corporation, lack of government primary schools, the plight of farmers including those engaged in the production of fish seeds, the rights of the LGBTQI community, etc. were discussed.

Later, the Commission also interacted with the representatives of civil society, NGOs and human rights defenders (HRDs). The Commission reiterated that it believes in working in tandem with SHRCs and the civil society representatives for the protection and promotion of human rights. NGO representatives and HRDs highlighted various issues like problems of the elderly, disabled persons, bedridden patients, etc.

Justice V. Ramasubramanian observed that the continued partnership of the NGOs and HRDs with the National Human Rights Commission will go a long way in strengthening human rights in the country.

They were also informed that they can file complaints of human rights violations online through hrcnet.nic.in

Dr. Justice Shameem Akther, Chairperson of the Telangana State Human Rights Commission, was present in all the meetings.

The New Indian Express

NHRC hearing in Hyderabad flags trafficking, custodial deaths, welfare lapses; 780 cases pending in Telangana

The proceedings were conducted across two division benches and a Full Commission sitting.

https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2025/Jul/30/nhrc-hearing-in-hyderabad-flags-trafficking-custodial-deaths-welfare-lapses-780-cases-pending-in-telangana

Khyarti Shah | Updated on: 30 Jul 2025, 9:45 am

3 min read

HYDERABAD: Apart from the trafficking of tribal women in Kumuram Bheem Asifabad district that was reported exclusively by this newspaper, wrongful detentions, caste-based exclusion, custodial deaths, and lapses in welfare delivery dominated the two-day sitting of the National Human Rights Commission (NHRC), which concluded in Hyderabad on Tuesday.

Over the course of the hearings, 109 cases from across Telangana were taken up, and 87 of them resolved. The proceedings were conducted across two division benches and a Full Commission sitting. Division Bench-I heard 36 cases, while Division Bench-II heard 51. Nineteen high-priority cases, including custodial death and compensation matters, were handled by the Full Commission.

The Commission took up the case of the trafficking of single, widowed and financially distressed tribal women under the pretext of marriage and employment, and selling them to buyers in other states. The report led to the dismissal of a police constable and the rescue of several victims.

Among the other cases heard was that of a juvenile who was kept in regular jail for 40 days before being transferred to a juvenile home. The NHRC directed that compensation should be paid to the family and called for a review of procedures followed by the police and child welfare authorities.

In Khammam, where a family had reportedly been subjected to a social boycott, the NHRC directed local police to ensure immediate action against caste-based exclusion.

Another case involved 48 students hospitalised due to food poisoning in government-run Gurukul schools. The NHRC instructed five concerned secretaries to submit detailed reports within four weeks.

In a fatal workplace accident at a DRDO-linked rocket propellant unit, four workers were killed. The Commission awarded `50 lakh each as compensation to three of the four families.

A case involving the rape and murder of a Dalit girl led to the release of `3.5 lakh as interim compensation. The Commission clarified that such compensation is based on the nature of the crime and not contingent upon final conviction.

One complaint was lodged by a Class 5 student regarding stray dog attacks in residential areas. In response, the NHRC asked local bodies to prepare an SOP to address animal control issues, particularly in vulnerable neighbourhoods. In other matters, tiger attacks in forest regions and failures in pension and nutrition delivery in hostels were also discussed.

Of the 109 cases heard, 22 concerned wosmen's safety, including cases of rape, sexual assault and trafficking. "Many daily complaints we receive involve gender-based violence and child rights violations," an NHRC official told TNIE, adding that the Commission receives around 250 complaints each day.

During the hearings, officials disclosed that 780 NHRC cases from Telangana remain pending. These include four deaths in police custody and approximately 30 in judicial custody. Nationwide, 35,685 cases are pending with the Commission.

The NHRC also reviewed a growing number of suo motu cases taken up in recent years: 17 in 2021, 33 in 2022, 77 in 2023, and 105 in 2024.

As of July 2025, over 50 such cases have been registered this year.

On the sidelines of the hearings, the NHRC held a closed-door meeting with the chief secretary, DGP and departmental secretaries. Officials were asked to submit status reports on action taken in response to previous NHRC advisories. Key topics included hostel conditions, education access for tribal children, pensions for senior citizens and persons with disabilities, and mechanisms for protecting women and children.

The Commission noted that several issues raised had appeared repeatedly in earlier sittings and warned of possible further inquiry if remedial action was delayed.

780 NHRC cases from TG remain pending

Officials disclosed that 780 NHRC cases from Telangana remain pending. These include four deaths in police custody and approximately 30 in judicial custody. Nationwide, 35,685 cases are pending with the Commission. The NHRC also reviewed a growing number of suo motu cases taken up in recent years.

NHRC

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने हैदराबाद में अपनी दो दिवसीय जन सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया: इस दौरान 109 मामलों की सुनवाई हुई

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

https://nhrc.nic.in/media/press-release/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A5%88%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%8B-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%94%E0%A4%B0

हैदराबाद: 29 जुलाई, 2025

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने हैदराबाद में अपनी दो दिवसीय जन सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया: इस दौरान 109 मामलों की सुनवाई हुई

आयोग द्वारा 9 मामलों में अनुशंसित 49.65 लाख रुपये में से, तेलंगाना सरकार द्वारा 22.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया और शेष 27.15 लाख रुपये का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया।

तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर समूहों के खिलाफ अपराध से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता का प्रसार किया ।

आयोग ने साझेदारी को मजबूत करने के लिए नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ भी बातचीत की।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने आज तेलंगाना राज्य में मानव अधिकार उल्लंघन के 109 मामलों की सुनवाई के बाद हैदराबाद में अपनी दो दिवसीय 'जन सुनवाई और शिविर बैठक' का समापन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी ने पीड़ितों, शिकायतकर्ताओं और अधिकारियों की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई की। इस दौरान महासचिव श्री भरत लाल, महानिदेशक (अन्वेषण) श्री आर.पी. मीणा, रजिस्ट्रार (विधि) श्री जोगिंदर सिंह और आयोग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जन सुनवाई के दौरान, आयोग की दोनों पीठों ने 90 मामलों की सुनवाई की। ये मामले आग लगने के कारण अस्पतालों में बच्चों की मौत, आवासीय क्षेत्रों में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, आग लगने की घटनाओं से हुई मौतें, बाघ के हमलों के मामले, आदिवासी महिलाओं का दुर्व्यापार, आदिवासी परिवारों को जबरन बेदखल करना, बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित करना, बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, पुलिस अत्याचार, आत्महत्या से होने वाली मौतें, दलित बंधु योजना निधि का दुरुपयोग, पारिवारिक पेंशन के मामले, प्राथमिक विद्यालयों की कमी, गुरुकुल स्कूलों में विषाक्त भोजन, कुपोषण के मामले, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना आदि से संबंधित थे।

आयोग ने मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के बाद उचित निर्देश पारित किए। दी गई कई महत्वपूर्ण राहतों में से कुछ इस प्रकार हैं:

• खम्मम जिले में जाति-आधारित उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार के एक मामले में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीण जाति-आधारित भेदभाव न करें या परिवार के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार लागू न करें।

• तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में लगभग 48 छात्रों की मौत और 886 खाद्य विषाक्तता की घटनाओं से जुड़े एक मामले में, आयोग ने सभी पाँच गुरुकुल स्कूलों के सचिवों को चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

• पुलिस द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तारी और लाठीचार्ज के एक अन्य मामले में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकार को संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और सहमति सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

• डीआरडीओ से जुड़ी एक रॉकेट प्रोपलेंट यूनिट में हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत से जुड़ी एक घटना में, चार में से तीन परिवारों को कुल 50 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है और आयोग ने शेष पीड़ित परिवार को भी राहत राशि देने का आदेश दिया है।

• बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे से संबंधित एक मामले में, जो पाँचवीं कक्षा के एक छात्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आयोग ने संबंधित अधिकारियों को इस खतरे को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया।

• आदिवासी महिलाओं के दुर्व्यापार से संबंधित एक मामले में, दोषी कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और दुर्व्यापार की शिकार कई आदिवासी महिलाओं को बचाया गया है।

बाद में, आयोग की पूर्ण पीठ ने 19 लंबित मामलों की सुनवाई की। इनमें से 9 मामलों में, आयोग ने पीड़ितों को 49.65 लाख रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफ़ारिश की। इसमें से 22.50 लाख रुपये तेलंगाना सरकार द्वारा पहले ही भुगतान किए जा चुके हैं। शेष 27.15 लाख रुपये का भुगतान करने पर यह सहमत हो गया है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, आयोग ने 29 मामलों को गुण-दोष के आधार पर बंद कर दिया। 2 मामलों को भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बंद कर दिया गया।

28 जुलाई, 2025 को मामलों की सुनवाई के बाद, आयोग ने 29 जुलाई, 2025 को तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर एक बैठक की। उन्हें सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में इस तरह से जागरूक किया गया कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। मानव अधिकारों का उल्लंघन न हो, इसके लिए निवारक और व्यवस्थित कदम उठाने पर ज़ोर दिया गया। इस बात पर ज़ोर दिया गया कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और व्यवसाय से प्रभावित मानव अधिकार संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, तेलंगाना के कई ज़िलों में मानव-पशु संघर्ष के कारण होने वाली मौतें, बड़ी संख्या में कुपोषण से पीड़ित बच्चे, अनुसूचित जाति निगम की समस्याएँ, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की कमी, मछली के बीज उत्पादन में लगे किसानों सहित किसानों की दुर्दशा, एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के अधिकार आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

आयोग ने राज्य के पदाधिकारियों द्वारा अपने निर्देशों के अनुपालन की सराहना की। अधिकारियों ने आयोग के समक्ष अपनी अच्छी कार्यप्रणाली प्रस्तुत की। उन्हें आयोग को समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ताकि मानव अधिकार पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित हो सके। आयोग के विभिन्न परामर्शों जैसे मानसिक स्वास्थ्य, बंधुआ मज़दूरी, भोजन और सुरक्षा के अधिकार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ज़ोर दिया गया। राज्य के मुख्य सचिव ने आयोग की सिफारिशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया।

बाद में, आयोग ने नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों (HRD) के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। आयोग ने दोहराया कि वह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखता है। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों और मानव संसाधन विकास (एचआरडी) ने बुजुर्गों, दिव्यांगों, बिस्तर पर पड़े मरीजों आदि की समस्याओं जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करने वालों के लिए वित्तीय सहायता की भी मांग की। गरीब बच्चों को उनके पहचान पत्र न मिलने की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया। आयोग ने राज्य में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उन्हें बिना किसी भय या पक्षपात के ऐसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन की इस टिप्पणी के साथ बातचीत समाप्त हुई कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ गैर-सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी) की निरंतर साझेदारी देश में मानवाधिकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्हें यह भी बताया गया कि वे hrcnet.nic.in के माध्यम से मानव अधिकार उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।

तेलंगाना राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति डॉ. शमीम अख्तर सभी बैठकों में उपस्थित थे।

इसके बाद, आयोग ने हैदराबाद, तेलंगाना में जन सुनवाई और शिविर बैठक के परिणामों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।

Janta Se Rishta

NHRC ने तेलंगाना में 31 अधिकार मामलों को बंद कर दिया |

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-closes-31-rights-cases-in-telangana-4180390

July 30, 2025

राज्य / तेलंगाना / NHRC ने तेलंगाना में...

Hyderabad हैदराबाद: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग The National Human Rights Commission (एनएचआरसी) ने 28 और 29 जुलाई को हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय खुली सुनवाई के दौरान 31 मामले बंद कर दिए। इनमें से 29 मामलों का निपटारा सुनवाई के बाद कर दिया गया, जबकि दो मामलों को अनुपालन और मुआवज़ा भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद बंद कर दिया गया। दो दिवसीय सत्र में 109 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें आग लगने की घटनाओं और बाघ के हमले में हुई मौतें, आदिवासी महिलाओं की तस्करी, आदिवासी परिवारों को जबरन बेदखल करना, बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना, बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, पुलिस ज्यादती, आत्महत्या और गुरुकुल स्कूलों में भोजन विषाक्तता जैसे मामले शामिल थे।

मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए, एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम ने कहा कि आयोग अब केवल मुआवज़े की सिफारिश करके मामलों को बंद नहीं करता। उन्होंने बताया, "अब हम उन्हें तब तक खुला रख रहे हैं जब तक हमें अनुपालन और भुगतान के प्रमाण नहीं मिल जाते।"पूरे आयोग ने 19 मामलों पर विचार किया। उनमें से नौ में, आयोग ने 49.65 लाख रुपये के मुआवज़े की सिफारिश की थी। इसमें से 22.50 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सरकार ने शेष 27.15 लाख रुपये का भुगतान और सबूत जमा करने का आश्वासन दिया है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने स्वतः संज्ञान मामलों में लगातार वृद्धि पर प्रकाश डाला, 2021 में 17, 2022 में 60, 2023 में 117, 2024 में 105 और इस वर्ष अब तक 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने इस वृद्धि का श्रेय आयोग द्वारा मीडिया पर कड़ी निगरानी को दिया। देश भर में, NHRC के समक्ष 34,685 मामले लंबित हैं। इनमें से 780 मामले तेलंगाना में हैं। अध्यक्ष ने कहा, "इनमें से चार पुलिस हिरासत के मामले हैं और 30 न्यायिक हिरासत के मामले हैं।" उन्होंने एक किशोर का उदाहरण दिया जिसे गिरफ्तार कर एक नियमित अदालत में पेश किया गया, जिसे 40 दिनों तक जेल में रखा गया था। उन्होंने कहा, "अभियोजन पक्ष का नतीजा चाहे जो भी हो, एक किशोर को 40 दिनों तक जेल में रखना अस्वीकार्य है। हमने परिवार को मुआवज़ा दिया है।"

आयोग ने महिलाओं, बच्चों, किसानों, अनुसूचित जातियों और छात्रावास के छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभागीय सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। अधिकारियों को पूर्व में जारी परामर्शों पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. न्यायमूर्ति शमीम अख्तर ने भी इसमें भाग लिया।एनएचआरसी ने बुजुर्गों, विकलांगों, अनाथों और वंचितों सहित कमजोर समूहों की सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव मांगने हेतु गैर सरकारी संगठनों, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों से मुलाकात की।

एनएचआरसी के सदस्य डॉ. न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी ने भी सुनवाई में भाग लिया।

समीक्षित प्रमुख मामले

खम्मम जाति उत्पीड़न मामला

पुलिस ने जाति-आधारित भेदभाव और ग्रामीणों द्वारा एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए कार्रवाई की।

गुरुकुल विद्यालयों में खाद्य विषाक्तता

48 छात्रों की मृत्यु और 886 खाद्य विषाक्तता के मामलों को देखते हुए, आयोग ने सभी पाँचों फुरुकुल समितियों के सचिवों को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

गलत गिरफ्तारी और पुलिस लाठीचार्ज

सरकार को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश।

रॉकेट प्रणोदक इकाई विस्फोट

चार मौतों में से तीन परिवारों को 50-50 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया गया है। आयोग ने चौथे परिवार को भुगतान का आदेश दिया।

कुत्तों के आतंक की शिकायत

कक्षा 5 के एक छात्र द्वारा उठाई गई। आयोग ने अधिकारियों को इस मुद्दे के समाधान के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया।

आदिवासी महिला तस्करी का मामला

तस्करी की गई कई महिलाओं को बचाया गया और दोषी कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

Janta Se Rishta

NHRC ने राज्य शासन में जवाबदेही का आह्वान किया

https://jantaserishta.com/amp/local/telangana/nhrc-calls-for-accountability-in-state-governance-4180851

By - Tulsi Rao | Update: 2025-07-30 12:58 GMT

हैदराबाद: भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हैदराबाद में दो दिवसीय शिविर और पूर्ण आयोग की सुनवाई का समापन किया, जिसमें तेलंगाना भर में मानवाधिकार उल्लंघन के कुल 109 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। ये सत्र संस्थागत सुधार, राज्य पदाधिकारियों के संवेदीकरण और सहयोगात्मक न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुए।

कार्यवाही के दौरान मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और विभाग प्रमुखों सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। विचार-विमर्श महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ-साथ राज्य शासन में प्रवर्तन तंत्र और जवाबदेही को मज़बूत करने पर केंद्रित था।

109 मामलों में से 90 की सुनवाई खुले सत्र में हुई। प्रमुख शिकायतों में अस्पतालों में आग से संबंधित बच्चों की मौत, जंगली जानवरों के हमले, आवारा कुत्तों की धमकियाँ, आदिवासी महिलाओं की तस्करी, पुलिस की ज्यादतियाँ, पेंशन से वंचित करना और बुनियादी ढाँचे की कमी शामिल थीं। उल्लेखनीय रूप से, दलित बंधु योजना के तहत गबन और गुरुकुल स्कूलों में प्रशासनिक खामियों को प्रणालीगत चिंता के क्षेत्रों के रूप में उजागर किया गया।

दो दिवसीय सुनवाई के दौरान आयोग के मुख्य निर्देशों में शामिल हैं: जाति-आधारित बहिष्कार (खम्मम): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद लागू भेदभावपूर्ण प्रथाओं को तत्काल समाप्त करना।

गुरुकुल स्कूल की लापरवाही के कारण सचिवों ने 48 मौतों और 886 खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के संबंध में चार सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। आयोग ने पुलिस कदाचार का संज्ञान लिया और तेलंगाना सरकार को गलत गिरफ्तारी और कथित लाठीचार्ज मामले पर विस्तृत दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

डीआरडीओ से जुड़ी इकाई में हुए औद्योगिक विस्फोट के संबंध में, पीड़ितों के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। आवारा कुत्तों के मुद्दे के संबंध में, अधिकारियों को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, तस्करी में संलिप्तता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी महिलाओं की तस्करी के दोषी पाए गए एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया, जिन्हें बाद में बचा लिया गया।

सुनवाई के समानांतर, एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने राज्य नेतृत्व के साथ एक रणनीतिक सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें समय पर अनुपालन, प्रणालीगत निवारक उपायों और बहु-क्षेत्रीय समन्वय पर ज़ोर दिया गया। अध्यक्ष भरत लाल ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संतुलन और व्यवसायों की मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों से संबंधित चिंताओं पर ज़ोर दिया।

पूर्ण आयोग की सुनवाई में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें शामिल हैं: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, बाल कुपोषण और शैक्षिक अंतराल, मानव-पशु संघर्ष में मौतें, एससी निगम में परिचालन संबंधी विफलताएँ, किसानों और मत्स्य बीज उत्पादकों की शिकायतें, और एलजीबीटीक्यूआई अधिकारों का संरक्षण।

पूर्ण आयोग के सत्र के दौरान, 19 मामलों की जाँच की गई और कुल 49.65 लाख रुपये के मुआवज़े की सिफ़ारिश की गई, जिसमें से 22.50 लाख रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 31 मामले बंद कर दिए गए, जिनमें से 29 मामले योग्यता के आधार पर और 2 मामले अनुपालन सत्यापन के बाद बंद किए गए।

एनएचआरसी ने संयुक्त निगरानी और निवारण के रास्ते बनाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के साथ भी बातचीत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के महासचिव ने राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया और नागरिकों को hrcnet.nic.in के माध्यम से डिजिटल रूप से शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया।

हितधारकों के साथ बातचीत के दौरान, कई चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिनमें शामिल हैं: वृद्ध और विकलांग नागरिकों के लिए सहायता; बिस्तर पर पड़े रोगियों के लिए सहायता; और बच्चों के लिए सामाजिक योजनाओं के दस्तावेज़ीकरण और पहुँच में देरी।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने नागरिक समाज के योगदान की प्रशंसा की और निडर एवं निष्पक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए एनएचआरसी की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

Janta Se Rishta

BRS ने रेवंत सरकार के तहत तेलंगाना में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर NHRC का रुख किया

https://jantaserishta.com/amp/local/telangana/brs-approaches-nhrc-over-human-rights-violations-in-telangana-under-revanth-government-4180091

By - Payal

Update: 2025-07-30 09:22 GMT

(एनएचआरसी) में एक याचिका दायर की है, जिसमें कांग्रेस सरकार पर व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन और तेलंगाना को भय के राज्य में बदलने का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने एनएचआरसी से रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कथित अत्याचारों, जिनमें लागाचेरला के किसानों पर कार्रवाई, फोन टैपिंग और बीआरएस कार्यकर्ताओं को राजनीतिक निशाना बनाना शामिल है, की व्यापक और स्वतंत्र जाँच का आदेश देने का आग्रह किया है। बीआरएस ने राज्य पुलिस को कानून के अनुसार निष्पक्ष पंजीकरण और मामलों की जाँच सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी करने की माँग की। इसने राजनीतिक निशाना बनाने पर प्रतिबंध लगाने, पीड़ितों को उचित मुआवज़ा देने और व्यवस्थागत सुधारों को लागू करने का भी अनुरोध किया।

एमएलसी दासोजू श्रवण, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरएस प्रवीण कुमार, पूर्व विधायक पटनम नरेंद्र रेड्डी, बीआरएसवी के प्रदेश अध्यक्ष गेलू श्रीनिवास यादव और बीआरएस कानूनी प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अपनी छह-पृष्ठ की याचिका में, पार्टी ने पुलिस के पक्षपात, मनमानी गिरफ्तारी, राजनीतिक प्रतिशोध और हाशिए पर पड़े समुदायों की उपेक्षा के उदाहरणों का हवाला दिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले नवंबर में एक फार्मा गाँव के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर पुलिस ने लागाचेरला में आदिवासियों पर हमला किया था। बीआरएस ने मंत्रियों, नौकरशाहों और विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए निगरानी उपकरणों के कथित दुरुपयोग की भी निंदा की और इसे संवैधानिक आपातकाल बताया। अन्य आरोपों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का राजनीतिकरण, चुनिंदा एफआईआर, बीआरएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से मीडिया लीक शामिल हैं। याचिका में प्रशासनिक लापरवाही और बाल श्रम के मामलों का हवाला देते हुए राज्य द्वारा संचालित कल्याणकारी आवासीय विद्यालयों में 100 से अधिक मौतों को भी उजागर किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए, श्रवण ने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना को एक निजी जागीर की तरह चला रहे हैं जहाँ कानून के शासन की जगह भय का शासन आ गया है। उन्होंने कहा, "आज जो हो रहा है वह शासन नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा पर एक संगठित हमला है।"

Janta Se Rishta

Telangana: हैदराबाद में एनएचआरसी की सुनवाई में मानव तस्करी पर चिंता

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-hearing-in-hyderabad-flags-trafficking-4179409

Subhi30 July 2025 10:14 AM

हैदराबाद: कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले में आदिवासी महिलाओं की तस्करी के अलावा, जिसकी इस अखबार ने विशेष रूप से रिपोर्ट की थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की दो दिवसीय बैठक में गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने, जाति-आधारित बहिष्कार, हिरासत में मौतें और कल्याणकारी योजनाओं में खामियों के मुद्दे छाए रहे। यह बैठक मंगलवार को हैदराबाद में संपन्न हुई।

सुनवाई के दौरान, तेलंगाना भर से 109 मामलों पर सुनवाई हुई और उनमें से 87 का निपटारा किया गया। कार्यवाही दो खंडपीठों और एक पूर्ण आयोग की बैठक में हुई। खंडपीठ-I ने 36 मामलों की सुनवाई की, जबकि खंडपीठ-II ने 51 मामलों की सुनवाई की। हिरासत में मौत और मुआवजे के मामलों सहित उन्नीस उच्च प्राथमिकता वाले मामलों को पूर्ण आयोग ने संभाला।

आयोग ने शादी और नौकरी के बहाने अविवाहित, विधवा और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त आदिवासी महिलाओं की तस्करी और उन्हें दूसरे राज्यों में खरीदारों को बेचने का मामला उठाया। रिपोर्ट के कारण एक पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया और कई पीड़ितों को बचाया गया।

Times of India

111 forest officers graduate in IGNFA’s largest 21st-century batch

https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/111-forest-officers-graduate-in-ignfas-largest-21st-century-batch/articleshow/123003715.cms

Jul 31, 2025, 03.37 AM IST

Dehradun: A record 111 Indian Forest Service (IFS) officers, including two from Bhutan, graduated from the Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA) on Wednesday, making it the largest batch to pass out in the 21st century since the academy's inception in 1938, according to officials.

The convocation ceremony held at the Forest Research Institute in Dehradun, had former Supreme Court judge and current National Human Rights Commission (NHRC) chairman, Justice V Ramasubramanian, as chief guest. Midhunmohan SB from Kerala received the Topper of the Batch award. The highest number of probationers was from Madhya Pradesh (17), followed by Uttar Pradesh (12) and Gujarat (6). IIT graduates Pranali Ramesh Umare, Rajat Suman, and Aditya Ratna joined the Uttarakhand cadre.

Addressing the officers, the chief guest urged them to uphold integrity, ecological responsibility, and constitutional values as they embark on their professional journey. He shared multiple anecdotes from history books and religious scriptures.

Reminding the young officers that they have joined ‘service, not employment', he said, "Swami Vivekananda said I hold every man a traitor, who, having been educated at the expense of the masses, pays not the least heed to them. You have become an all-India service officer and not an employee. Our ancestors made a very clear distinction between people who take up jobs, who go for employment, and the people who enter service."

Indicating the importance of ensuring a worthy career graph, he added, "Today, as an officer, you might be experiencing a sense of achievement at your convocation ceremony, but during your service period, you will have to perform in a manner that gives you a sense of fulfilment at the time of retirement."

Meanwhile, director of the academy, Jagmohan Sharma, said that is the first batch to pass out after the change in the training course pattern in 2023, after which it included an enhanced focus on artificial intelligence and climate change, among others.

Incidentally, President Droupadi Murmu, who was chief guest at the convocation in April 2024, had indicated revising the IGNFA training curriculum with the changing climate and its effects on the planet. TOI had highlighted the President's piece of advice and concern that reverberated in her speech to the young officers at the IGNFA.

Amar Ujala

Dehradun: देश को मिले 109 आईएफएस अफसर, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से, पास आउट होने वाला सबसे बड़ा बैच

https://www.amarujala.com/dehradun/dehradun-news-india-got-109-ifs-officers-pass-out-from-forest-research-institute-2025-07-30?pageId=2

माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 30 Jul 2025 08:32 PM IST

सार

देहरादून

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला भारतीय वन सेवा का 2023-2025 बैच 21वीं सदी का सबसे बड़ा बैच रहा, जिसमें भूटान के दो और देश के विभिन्न राज्यों के 109 अफसरों ने प्रशिक्षण (कुल 111) प्राप्त किया।

विस्तार

देश को भारतीय वन सेवा के 109 अफसर मिले। इसमें सबसे अधिक आईएफएस मध्य प्रदेश (17) को मिले हैं। वन अनुसंधान संस्थान के सभागार में बुधवार को आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने अफसरों को प्रमाणपत्र और मेडल सौंपे। सर्वांगीण उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार केरल कैडर के मिधुनमोहन एसबी को मिला है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला भारतीय वन सेवा का 2023-2025 बैच 21वीं सदी का सबसे बड़ा बैच रहा, जिसमें भूटान के दो और देश के विभिन्न राज्यों के 109 अफसरों ने प्रशिक्षण (कुल 111) प्राप्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा करने पर शुभकामना देने के साथ सीख भी दी। उन्होंने कहा कि आगे नौकरी करेंगे, उस दौरान नियमों को कभी न तोड़ें।

नियम तोड़ने पर तत्काल लाभ हो सकता या नियमों का पालन करने पर कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन आखिरी में नियम तोड़ने वाले को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जबकि नियमों का पालन करने वाले आगे सुखद परिणाम हासिल करता है। इससे पूर्व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के निदेशक डॉ.जगमोहन शर्मा ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और 14 मित्र राष्ट्रों के 367 वन अधिकारियों ने अब तक संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि इस बैच में 22 महिला आईएफएस प्रशिक्षु शामिल हैं। 50 अधिकारियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दौरान वानिकी के साथ ही शासन के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा समेत विभिन्न संस्थानों के अधिकारी मौजूद थे।

इन राज्यों को मिले आईएफएस

आंध्र प्रदेश- पांच
असम, मेघालय- तीन
बिहार- दो
छत्तीसगढ़- चार
कर्नाटक- छह
गुजरात- छह
हरियाणा- तीन
हिमाचल - पांच
मध्य प्रदेश- 17
महाराष्ट्र- पांच
ओडिशा- छह
पंजाब- एक
राजस्थान- चार
तमिलनाडू- छह
तेलंगाना- एक
त्रिपुरा- एक
उत्तर प्रदेश- 12
उत्तराखंड- तीन
प.बंगाल- छह
एजीएमयूटी- सात
केरल - 2
झारखंड - 4
भूटान - 2

ये पुरस्कार भी दिए गए

सर्वश्रेष्ठ वानिकी- पृथ्वीराज- उत्तर प्रदेश

मुख्य वानिकी विषयों में टॉपर- शोभित जोशी- मध्य प्रदेश

हिल स्मृति पुरस्कार- शोभित जोशी- मध्य प्रदेश

पी श्रीनिवास स्मृति पुरस्कार- अजय गुप्ता- मध्य प्रदेश

संजय कुमार सिंह स्मृति पुरस्कार- नीलम- उत्तर प्रदेश

ईपी जी वन्यजीव प्रबंधन पुरस्कार- अजय गुप्ता- मध्य प्रदेश

केपी सग्रेया श्रेष्ठ वानिकी पुरस्कार - मिधुनमोहन एसबी

नीलगिरी वन्यजीव क्लब पुरस्कार- शुभम सिंह- कर्नाटक

सुलोचना नायडू स्मृति पुरस्कार- अजय गुप्ता- मध्य प्रदेश

कार्ययोजना अभ्यास के लिए डीएच कुलकर्णी पुरस्कार - नीलम एम- उत्तर प्रदेश

बीएन गागुली शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार - मिधुमोहन एसबी

केएम तिवारी स्मृति पुरस्कार - मिधुमोहन एसबी

वरिष्ठ वनपाल पुरस्कार- नीलम एम- उत्तर प्रदेश

द स्पिरीट आफ 1982 प्रथम - पृथ्वीराज केएसबी- उत्तर प्रदेश

द स्पिरीट आफ 1982 द्वितीय - शुभम सिंह- कर्नाटक

Jagran

देश को मिले 109 आइएफएस अफसर, केरल के मिधुनमोहन ने किया टाप

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 2023-25 बैच के दीक्षांत समारोह में 109 आईएफएस अधिकारी पास हुए। मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 17 अधिकारी मिले। केरल के मिधुनमोहन को सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों को नैतिक दायित्वों का पालन करने की सीख दी। कुल 111 अधिकारियों में 22 महिलाएं शामिल हैं।

https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-109-ifs-officers-join-nation-from-ignfa-midhun-mohan-tops-23999106.html

By Suman semwal Edited By: Nirmala Bohra Updated: Wed, 30 Jul 2025 08:33 PM (IST)

HighLights

109 नए आईएफएस अधिकारी देश को मिले

केरल के मिधुनमोहन बने टॉपर

मध्य प्रदेश को सर्वाधिक 17 अधिकारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) के वर्ष 2023-2025 बैच के दीक्षा समारोह के साथ ही देश को 109 आइएफएस अफसर मिल गए। जो अब अपने-अपने कैडर के राज्य में युवा वनाधिकारी के रूप में सेवा देंगे।

पासआउट होने वालों में आइएफएस के अलावा दो प्रशिक्षु अधिकारी भूटान के भी हैं। सर्वाधिक 17 अफसर मध्य प्रदेश को मिले हैं। वहीं, दीक्षा समारोह में सर्वांगीण उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार केरल कैडर के मिधुनमोहन एसबी को मिला।

बुधवार को वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) के दीक्षांत सभागार में आइजीएनएफए के दीक्षा समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन के किया। उन्होंने प्रशिक्षु आइएफएस अधिकारियों को अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान किए गए प्रदर्शन के अनुरूप अवार्ड प्रदान किए।

युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रामसुब्रमण्यन ने प्रशासनिक दायित्वों के साथ नैतिक एवं सांविधिक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्य करने की सीख दी।

अकादमी के निदेशक डा. जगमोहन श्रम ने कहा कि पासआउट होने वाले कुल 111 प्रशिक्षु अधिकारियों में 22 महिला आइएफएस अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बैच के 50 अधिकारियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंकों से आनर्स डिप्लोमा प्राप्त किया है। इस अवसर पर एफआरआइ की निदेशक डा. रेणु सिंह समेत विभिन्न केंद्रीय और राज्य के वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यवार हिस्से आए युवा आइएफएस अधिकारी

राज्य, संख्या

मध्य प्रदेश, 17

उत्तर प्रदेश, 12

केंद्र शासित प्रदेश, 08

पश्चिम बंगाल, 06

गुजरात, 06

ओडिसा, 06

तमिलनाडु, 06

कर्नाटक, 06

आंध्र प्रदेश, 05

हिमाचल प्रदेश, 05

महाराष्ट्र, 05

झारखंड, 04

छत्तीसगढ़, 04

राजस्थान, 04

उत्तराखंड, 03

असम (मेघालय), 03

हरियाणा, 03

बिहार, 02

केरल, 02

पंजाब, 01

तेलंगाना, 01

त्रिपुरा, 01

इन्हें मिला अवार्ड

केंद्र सरकार के पुरस्कार

सर्वांगीण उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार : मिधुनमोहन एसबी (केरल)

सर्वश्रेष्ठ आल राउंड फारेस्टर : पृथ्वीराज केएस एसबी (उत्तर प्रदेश)

मुख्य वानिकी विषयों में टापर : शोभित जोशी (मध्य प्रदेश)

पी श्रीनिवास स्मृति पुरस्कार : अजय गुप्ता (मध्य प्रदेश)

संजय कुमार सिंह स्मृति पुरस्कार : नीलम (उत्तर प्रदेश)

डोनर पुरस्कार

हिम स्मृति पुरस्कार : शोभित जोशी (मध्य प्रदेश)

डीसी अग्रवाल पुरस्कार : मथुआरसी एम (पश्चिम बंगाल)

ईपीजी वन्यजीव प्रबंधन पुरस्कार : सोनू कुमार (बिहार)

आरएन माथुर स्मृति पुरस्कार : अजय गुप्ता (मध्य प्रदेश)

केपी सग्रेया श्रेष्ठ फारेस्टर पुरस्कार : मिधुनमोहन एसबी (केरल)

नीलगिरि वन्यजीव क्लब पुरस्कार : शुभम सिंह तंवर (कर्नाटक)

सुलोचना नायडू स्मृति पुरस्कार : अजय गुप्ता (मध्य प्रदेश)

The New Indian Express

CM stand unacceptable, law on honour killing must: CPM politburo member

“Political parties should take a firm stand regarding dowry harassment. Film actors should announce that they will not receive dowry,” Vasuki said.

https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2025/Jul/31/cm-stand-unacceptable-law-on-honour-killing-must-cpm-politburo-member

Express News Service | Updated on: 31 Jul 2025, 8:12 am

2 min read

KANNIYAKUMARI/MADURAI: CPM politburo member U Vasuki on Wednesday said the state government should enact a law to prevent castebased killings.

Speaking to reporters, Vasuki, who is also the all India vice president of the All India Democratic Women’s Association (AIDWA), said, “Chief Minister M K Stalin’s stand that existing laws are adequate to prevent caste-based killings is not acceptable.”

A special session of the TN Assembly should be convened to enact separate legislation as crime and atrocities against women and children are increasing in the state, she added.

“Political parties should take a firm stand regarding dowry harassment. Film actors should announce that they will not receive dowry,” Vasuki said.

Meanwhile, addressing reporters in Madurai, A Kathir, executive director of Evidence — an NGO working for rights of the SC/ST community — said that the National Law Commission of India, National Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Women and National Commission for Minorities should come together and prepare a draft model for a special Act against honour killing, as per the apex court’s guidelines.

“The Supreme Court has given 20 guidelines in the Shakti Vahini vs Union of India case on March 27, 2018, to prevent honour killings. One such guideline instructs states to implement a special Act against honour killings. When CM Stalin was the opposition leader, he said that the DMK will enact a separate law against honour killings.However, after coming to power, he has said that there is no need for such a law,” Kathir said.

The SC must take suo motu cognisance against states that have not adopted guidelines issued by it in the 2018 case, he added.

Nainar, Kanimozhi react

Three days after the caste-based killing of Dalit youth C Kavin Selvaganesh, Tamil Nadu BJP president and Tirunelveli MLA Nainar Nagenthran on Wednesday issued a statement condemning the incident and urging the state government to act against such crimes. Calling the killing an inhuman act, he also expressed condolences to the family.

“I urge the Tamil Nadu police and the ruling DMK government to take appropriate measures to prevent such continuing cases of caste atrocities, sexual violence, drug-related issues, murders and robberies in the state,” he said. The delayed response from prominent leaders, including Nagenthran, drew criticism on social media.

Meanwhile, in a social media post on Wednesday, DMK MP from Thoothukudi, Kanimozhi Karunanidhi, expressed shock and grief over the honour killing. CPI state president R Mutharasan also condemned it, demanding stringent punishment for the accused and urging the state to enact a separate law to prevent honour killings.

The News Agency

Supreme Court Upholds Acquittals of Moninder Singh Pandher and Surendra Koli in Nithari Killings Case

https://www.thenewsagency.in/india/supreme-court-upholds-acquittals-of-moninder-singh-pandher-and-surendra-koli-in-nithari-killings-case/

Mohit Dubey | 3 min read

New Delhi, July 31 (TNA) The Supreme Court of India, in the infamous 2006 Nithari serial killings case, granted relief to the accused Moninder Singh Pandher and Surendra Koli by upholding their acquittals in multiple cases related to the crimes.

A bench led by Chief Justice of India BR Gavai, along with Justices Satish Chandra Sharma and K Vinod Chandran, dismissed 14 appeals filed by the Central Bureau of Investigation (CBI), the Uttar Pradesh government, and victim families that challenged the acquittal orders issued by the Allahabad High Court in 2023. The Supreme Court found “no perversity” in the High Court’s judgment, which had overturned the earlier convictions based largely on circumstantial evidence that was ruled insufficient to prove guilt “beyond a reasonable doubt.”

Key legal issues included lapses in the investigation, especially concerning the recovery of critical evidence such as human skulls and victims’ belongings.

The Court emphasised that under Section 27 of the Indian Evidence Act, recoveries must be made following a voluntary statement from the accused and from locations exclusively known to them for the evidence to be admissible. The investigation had failed on these points, weakening the prosecution’s case.

The verdict has been met with mixed reactions, as families of the victims and victims’ rights advocates express distress over the acquittals amid criticism of investigative agencies for procedural lapses and mishandling of vital evidence.

While Moninder Singh Pandher was acquitted in all cases against him, Surendra Koli, though acquitted in 12 of the Nithari cases, will continue to remain in jail due to a separate life sentence related to the 2005 murder of a minor girl named Rimpa Haldar.

This Supreme Court decision marks the closure of a long and painful chapter in one of India’s most gruesome criminal cases, which involved the abduction, rape, and murder of children and young women in the Nithari village area of Noida, Uttar Pradesh.

The verdict has been met with mixed reactions, as families of the victims and victims’ rights advocates express distress over the acquittals amid criticism of investigative agencies for procedural lapses and mishandling of vital evidence.

• December 16, 2006: Two Nithari village residents report the location of missing children's remains, leading to the discovery near Moninder Singh Pandher's house in Noida.

• December 29, 2006: Police find skeletal remains of eight children in the drainage behind Pandher's house; suspects Moninder Singh Pandher and his domestic help Surinder Koli are arrested.

• December 30-31, 2006: More skeletal remains found; political pressure mounts, leading to suspension of two beat constables.

• January 5, 2007: Uttar Pradesh Police take Pandher and Koli for narco-analysis tests in Gandhinagar.

• January 10, 2007: Central Bureau of Investigation (CBI) takes over the investigation.

• January 11-12, 2007: CBI discovers about 30 more bones and interrogates the accused.

• January 20, 2007: Uttar Pradesh government files a report to the National Human Rights Commission (NHRC).

• February 8, 2007: Special CBI court sends Pandher and Koli to 14 days of CBI custody.

• February 12, 2007: NHRC forms a committee to study the case.

• March 22, 2007: CBI files the first chargesheet; Pandher faces lesser charges, Koli is charged with murders, rape, and kidnapping.

• May 1, 2007: Parents of victims move court against CBI for letting Pandher off in kidnapping and murder charges.

• September 6, 2007: Body of Jatin Sarkar, father of a victim, found in West Bengal.

• November 1, 2007: Supreme Court issues notice to CBI on allegations they shielded Pandher.

• December 13, 2007: Charges framed against Pandher for the rape and murder of two teenagers.

• February 12, 2009: Special Judge pronounces Pandher and Koli guilty of rape and murder, sentencing them to death.

• January 7, 2010: Supreme Court upholds the death sentence of Surinder Koli.

• October 16, 2023: Allahabad High Court acquits both Pandher and Koli, citing lack of evidence; acquittals upheld by Supreme Court in 2025.

Deccan Chronicle

Malvika Kaul | The Emerging Realities Of Ageing, And How It Affects India

https://www.deccanchronicle.com/opinion/dc-comment/the-emerging-realities-of-ageing-and-how-it-affects-india-1894626

Malvika Kaul 30 July 2025 10:22 PM

India is at the cusp of an unprecedented and irreversible demographic transition

India is at the cusp of an unprecedented and irreversible demographic transition. The proportion of elderly citizens is growing steadily. As per the Census of India reports, elderly persons (above 60 years) rose from 24.7 million in 1961 to 103.8 million by 2011, representing more than a four-fold increase in just 50 years. In 2022, the number of people over the age of 60 was close to 149 million, comprising 10.5 per cent of the total population.

An increase in life expectancy and a declining fertility rate in recent decades has contributed to this trend. Experts suggest that by 2050, nearly 20 per cent of the Indian population will be over the age of 60, amounting to over 347 million individuals. For policymakers, healthcare professionals and care-giving institutions, this has emerged as a complex challenge involving issues of social security, healthcare, economic dependency, mental health and caregiving. It has forced a rethink on existing insurance and pension systems, health infrastructure and a review of social support models.

Globally, individuals are living longer than ever before. In 2018, for the first time in history, people aged 65 years and above outnumbered children under the age of five. By 2050, the number of people aged 60 and above is expected to more than double. Significantly, in developing countries, ageing is taking place at an exceptional pace. While the doubling of the elderly population took nearly 150-200 years in developed countries, it has happened in just 50-70 years in developing countries like India.

Addressing such developments requires large-scale studies and multi-level consultations. In 2017, the ministry of health and family welfare launched the nationwide survey, the Longitudinal Ageing Study in India (LASI). This population-based survey investigates the health, economic, and social determinants and consequences of population ageing in India. This survey could be considered the world's largest, offering a database for designing policies and programmes for the aged population.

Data from LASI indicated that the southern states have the highest proportions of older adults. They also appear to be putting systems in place. States like Kerala have already allocated five per cent of the budget to palliative care and evolved frameworks to safeguard the autonomy of senior citizens. In 2024, the port city of Kochi became the first city in India to be a member of WHO’s Global Network for Age-friendly Cities and Communities. Here streets have been redesigned with ramps, handrails, and tactile paving for better mobility. Public parks have exercise zones and senior-friendly seating.

The city now offers age-friendly apps and digital literacy workshops to senior citizens. The scientific surveys have helped us infer certain realities about the aged: There is a rise in nuclear families that has resulted in greater number of elderly living alone, without the support of their children. When young people migrate, the elderly are left alone. They are more vulnerable to loneliness, depression, abuse and isolation. As the traditional support systems have substantially eroded, more elderly individuals are victims of ageism. In recent years, violence and abuse of elderly have often been reported in the media.

In 2007, the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act allowed the elderly “unable to maintain themselves” to take legal action against adult children or grandchildren who fail to provide them with basic necessities such as housing, food, clothing, and medical care. This law acknowledged the harsh reality of many old people, including widows. However, enforcement of such a law has been difficult. Several senior citizens are not even aware of such a law. Considering this silent crisis, there is an urgency to overhaul the healthcare systems today. The elderly face heightened risk of various disabilities, cognitive decline and mobility limitations. We need a comprehensive healthcare package for the elderly which includes adult vaccinations, rehabilitative services and mental health care and palliative support.

For women, who often live longer and are more vulnerable, specific policy support is required. Some of the concerns for elderly population were elaborated by senior bureaucrats, researchers, thought leaders and care support organisations at a seminar “Ageing in India: Actionable Solutions” in December last year in New Delhi by the Sankala Foundation, a research organisation. Besides the Niti Aayog and the ministry of social justice and empowerment, the seminar was supported by the National Human Rights Commission (NHRC). In recent years, the NHRC has focused on monitoring and advocating the rights of senior citizens, ensuring all elderly prisoners are also covered by health insurance schemes, and in improving the functioning of old age homes. Increasingly, experts have recommended for the creation of an integrated National Plan on Elderly Care that would include comprehensive geriatric care.

Many quote models followed in places like Hong Kong, where family members are trained to care for elderly relatives. Some advocate for integrating old-age homes within local neighbourhoods (like it is in Shanghai) to enhance inclusion. Importantly, a large group of experts have called for leveraging the “silver dividend” ensuring that elderly care becomes part of national development. The elderly bring a wealth of experience, knowledge, and cultural depth that can be harnessed to enrich communities and contribute to social and economic development. This requires building a robust senior care economy focused on specialised healthcare, elder-friendly tourism and recreational activities.

Later this week, on August 1, several of the country’s experts on the issue of ageing will share their vision on how to respond to the current challenges at the national conference on “Ageing in India: Emerging Realities, Evolving Responses”. They will help reimagine systems that not only support care for the aged but promise them a life of dignity, security and purpose The writer is a director with the Sankala Foundation, an NGO which works in climate change, wildlife conservation and public health (Source : Deccan Chronicle)

Live Law

Inclusion Of Leprosy As Ground For Divorce `Embarrassing', Says Supreme Court

https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-discriminatory-laws-leprosy-as-ground-for-divorce-embarrassing-union-states-to-take-remedial-action-299351

Debby Jain 30 July 2025 5:57 PM (5 mins read

The Supreme Court today urged the Union of India as well as States/Union Territories to take urgent remedial action against laws, rules, regulations, etc. which are discriminatory and/or derogatory towards leprosy-affected or cured persons. A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi was dealing with a public interest litigation initiated in 2010, where it earlier directed the States to form a Committee to identify provisions in various laws, etc. which discriminate against leprosy-affected or cured persons, and take steps for their removal so that they conform with constitutional obligations.

Today, the Court noted that some states had filed their compliance affidavits regarding constitution of the Committees, but some remained to do the needful. As such, 2 weeks' further time was given to the non-compliant states to comply with the Court's earlier direction. Further, Chief Secretaries of the State governments were asked to file status reports on the follow-up action taken by them pursuant to recommendations of their respective Committees.

Insofar as the National Human Rights Commission was found to have independently examined the issue, the Court ordered that the Secretary of NHRC shall furnish the details to the Court after getting approval from NHRC Chairman. The bench also advised that the states need not wait for particular Assembly sessions to carry out necessary changes in their laws, etc. "For this purpose, a one-day session can be [called]...to eliminate these provisions...it will send a very good signal...rules and regulations, Cabinet can sit and resolve", said Justice Kant.

Sr Advocate and UP AAG Garima Prashad informed the Court that Uttar Pradesh has identified 3 laws which need to be "corrected". Likewise, a counsel appearing for Rajasthan government informed that 2 laws have been identified and requisite recommendation has been made. In particular, the bench asked about the Union's response, which was represented by Additional Solicitor General Aishwarya Bhati. The petitioner had previously informed that 4 Central Acts were amended in 2019, but still, there were more than 100 legislations where discriminatory provisions existed. The states' figure, on the other hand, stood at 145 legislations.

For Withstanding Media Pressure "The most serious...we don't want to use the word, but how embarrassing it is...you have created a ground for taking divorce", lamented Justice Kant to ASG Bhati. Ultimately, the matter was adjourned to await the Union and states' response. It is worthwhile to mention that in 2019, the Central Government notified the Personal Laws (Amendment) Act 2019 to remove leprosy as a ground for divorce. To this end, it amended 5 Acts: (i) the Divorce Act, 1869, (ii) the Dissolution of Muslim Marriage

Act, 1939, (iii) the Special Marriage Act, 1954, (iv) the Hindu Marriage Act, 1955, and (v) the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. Background As per claims made in the petition by Federation of Leprosy Organization (petitioner), 'leprosy' was initially considered a dreaded disease because it was incurable, highly contagious, and infectious.

During that time, there was a need to segregate the leprosy patients from society at large, and therefore, the Indian Lepers Act, 1898, was enacted to provide segregation of leprosy-affected persons. This Act contained draconian provisions against leprosy patients, such as arrest without warrant, putting them in leprosy asylums and restraints on property or voting rights. Such persons were also not allowed to seek employment. In a breakthrough in 1979, the Multi-Drug Therapy (MDT) was developed as a cure for leprosy at any stage. Following 1981, it was extensively used in India to completely cure leprosy.

As a result of a declaration by the World Health Organization that leprosy is fully curable and not at all contagious, the 1898 Act was repealed. In 2004, the petitioner wrote to the state governments to remove provisions discriminatory towards leprosy-affected or cured persons from their laws, orders, etc., but they continued to remain. Appearance: Senior Advocate Vinay Garg; ASG Aishwarya Bhati; Senior Advocate and UP AAG Garima Prashad; AoRs Rashmi Nandakumar and Mayuri Raghuvanshi Case Title: FEDERATON OF LEPY.ORGAN.(FOLO) . AND ANR. Versus UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 83/2010 (and connected case)

Deccan Herald

Call assembly session or enact ordinance to remove discriminatory laws against leprosy patients: SC

"Where it is not possible to call for a session, an ordinance can be enacted. The state government will be doing great service to them," the bench said.

https://www.deccanherald.com/india/call-assembly-session-or-enact-ordinance-to-remove-discriminatory-laws-against-leprosy-patients-sc-3657297

PTI Last Updated : 30 July 2025, 22:35 IST

New Delhi: The Supreme Court on Wednesday called upon the states to summon special one-day assembly sessions or enact an ordinance to amend discriminatory, derogatory and demeaning provisions in various laws against leprosy-affected persons. A bench of Justices Surya Kant and Joymalya Bagchi said the Centre and states will be doing great service to these people by removing such discriminatory and demeaning provisions of law. "States can call upon a special assembly session or a one-day session instead of waiting for a regular monsoon session or winter session and remove or amend the discriminatory provisions against leprosy-affected persons. "Where it is not possible to call for a session, an ordinance can be enacted. The state government will be doing great service to them," the bench said. The top court was dealing with a batch of PILs, including one initiated in 2010 in which the bench had earlier directed the states to form a committee to identify provisions in various laws, etc., which discriminate against leprosy-affected or cured persons, and take steps for their removal so that they conform to constitutional obligations.

Earlier, the court had said it was informed that there might be more than 145 state legislation where such objectionable provisions were still subsisting. The apex court on Wednesday urged the states to take remedial action and said, "It has been brought to our notice, now let's take remedial action. It is not the court's job but the state government's to do it." The bench asked the states, which have not filed the status report, to do so by October and said the National Human Rights Commission, which is also dealing with the issue, may submit a report with due permission from the chairperson. Additional advocate general Garima Prashad informed the bench that the Uttar Pradesh government has identified three laws which need to be "corrected". Similarly, Uttarakhand and Rajasthan government lawyers submitted that they have filed their status reports and identified a couple of laws and necessary actions have been taken. "The most serious of all...we don't want to use the word but see how embarrassing it is. Leprosy was one of the grounds for taking divorce", Justice Kant told Additional Solicitor General Aishwarya Bhati. The top court sought a response from the Centre and its status report on the issue. On May 7, the top court noted that these provisions are of wide range illustratively from prohibition against holding elected offices to leprosy being a ground of divorce before the family laws came to be amended by the Parliament, during pendency of these proceedings, through the Personal Laws (Amendment) Act, 2019, which came into force with effect from

February 21, 2019. "We are informed that there might be more than 145 state legislations, besides some Regulations/Rules/Bye-Laws/ Executive instructions operating in different fields, where the offending provisions are still subsisting," the top court had said ". The court said it is not sure as to how many states have taken it seriously and earnestly and have taken any effective step to remove the offending and discriminatory expressions from their state laws so as to bring them in conformity with the Constitution.

"We, therefore, deem it appropriate to direct the chief secretaries and the law secretaries of all the states to immediately constitute a Committee of three officers from the law and justice department of each State, preferably to be headed by an officer in the rank of principal district judge," the bench had said, and directed that the states may request Chief Justice of the high court to provide an officer in the rank of district judge for a short duration (on deputation). It had said the committee shall identify all the state laws, pre or post Constitution, where the discriminatory expressions related to leprosy-affected or cured persons are still part of the statute book and such regulations, statutory rules or bylaws where similar provisions have been incorporated, shall also be identified. The petitioners, including the Federation of Leprosy Organisation (FOLO) and legal think-tank ‘Vidhi Centre for Legal Policy’, have contended that over a hundred provisions existed, both in central and in state laws which discriminated against persons affected by leprosy in ways that caused stigmatisation and indignity to them. The PIL filed by Vidhi Centre for Legal Policy in 2017 contended a provision of the Orissa Municipal Corporation Act, 2003, disqualified a person affected by leprosy from contesting elections for the post of corporator of the Municipal Corporation on account of his or her affliction by leprosy. Similarly, the PIL said the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, disqualified a leprosy victim from contesting elections for the post of a Panch or any other member of the Panchayati Raj Institution.

Millennium Post

Agony behind Easy Credit

Mushrooming of unregulated lending apps in India has entrapped millions in predatory debt, and as regulators falter, the judiciary has emerged as a vital nudge for safeguarding borrowers' dignity and justice

https://www.millenniumpost.in/opinion/agony-behind-easy-credit-620966

BY Sanjay Gupta30 July 2025 9:50 PM

Sanjay Gupta30 July 2025 9:50 PM

The recent oral observation by a Supreme Court division bench comprising Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi—stating that the Reserve Bank of India (RBI), rather than the courts, is the appropriate forum for addressing grievances related to unregulated lending—brings to light a telling paradox. The story of India's financial revolution has been one of innovation and inclusion—of smartphones enabling rural banking, Aadhaar linking millions to subsidy schemes, and digital wallets becoming daily essentials. Yet, lurking beneath this impressive surface is a growing and insidious crisis—an explosion of unregulated personal loans, algorithm-driven disbursals, and coercive recovery mechanisms that are quietly trapping millions in cycles of debt.

Over the past five years, India has witnessed an unprecedented rise in app-based lending platforms—many of them operating without proper licenses, often floating under the regulatory radar by using shell entities or foreign servers. While RBI has issued guidelines on digital lending and appointed working groups, enforcement remains spotty. Lenders, especially non-banking financial companies (NBFCs), often deploy aggressive field recovery agents who resort to threats, coercion, and public shaming—tactics reminiscent of loan sharks. The distress is real, widespread, and disturbingly invisible to policymakers. The architecture of our financial system today allows a salaried employee in a tier-2 city to receive five separate personal loans from as many fintech apps in less than an hour. But if that same individual finds himself unable to pay after a health crisis or a job loss, his recourse to restructuring, counselling, or legal remedy is murky at best.

In rural and semi-urban India, the situation is worse. With weak institutional presence and limited financial literacy, many borrowers are lured into taking multiple concurrent loans with attractive EMI schemes and "no documentation" offers. The problem is not just the loan—it is the absence of full disclosure, the lack of cooling-off periods, the opacity of interests compounding mechanisms, and the absence of centralised borrower information. These factors combine to push families into unmanageable liabilities. The human cost is profound. What makes matters worse is the behaviour of mainstream institutions. S Singhal, retired deputy general manager of a leading nationalised bank, informs, "Many scheduled banks, despite enjoying public trust, participate in this high-speed, opaque lending ecosystem through partnerships with NBFCs and fintech aggregators. They disburse loans without a personal interaction or risk assessment

beyond a credit score. They do not ask if the borrower has other liabilities, or whether a spouse is aware of the loan being taken."

Various credit information companies and bureaus, too, are part of this web. Borrowers frequently complain that once they fall into arrears with a single lender, their credit reports get locked in a negative loop—even if they settle the dues later. What, then, is the role of the regulator? Dr S Balwada, advocate-on-record, Supreme Court of India, advises, "The RBI's mandate includes safeguarding the interests of depositors and ensuring fair practices. But when its grievance redress portals redirect complainants to the very banks or NBFCs they are battling, the system becomes a circle of abdication. The average borrower neither has the legal sophistication to file consumer complaints nor the time to approach a High Court. Most quietly give up—and some, tragically, give in."

Justice Surya Kant's observation—that disputes involving lending practices are better handled by financial regulators—is institutionally sound. Courts, after all, are not designed to perform the day-to-day oversight functions of economic bodies like the Reserve Bank of India, adds Balwada In lending matters, even a well-reasoned acknowledgment of systemic lapses can act as a catalyst for policy reform. Often, the judiciary's voice lends legitimacy and urgency to public grievances that otherwise remain unheard in regulatory corridors. When borrowers feel voiceless, and institutions remain unresponsive, the courts serve as the last democratic forum. Their role is not to rewrite policy, but to ensure that justice is not a casualty of red tape or bureaucratic opacity.

Meanwhile, the government's silence is even more deafening. No major legislative attempt has been made to create a unified Financial Consumer Protection Code. The Debt Recovery Tribunals are overburdened and under-resourced. The financial literacy campaigns are more symbolic than structural. And institutions like the National Human Rights Commission have yet to treat aggressive debt collection practices as potential human rights violations. Unless institutions—regulators, ministries—begin to treat borrower protection as a central pillar of economic justice, the silent debt trap will continue to devour the very citizens financial inclusion was meant to empower. More importantly, public sector banks must lead by example. If nationalised banks, backed by the state, cannot uphold ethical lending practices, what incentive do private lenders have to do better? It is a reminder that financial dignity is as important as financial access.

The writer is an accredited journalist. Views expressed are personal

The Week

Values education is crucial for India's youth, said NHRC Secretary General Bharat Lal. He emphasised integrating ethics, life skills, and a strong moral compass into the education system for holistic development and tackling modern challenges

https://www.theweek.in/education/latest/2025/07/30/the-week-education-conclave-teach-values-not-just-degrees-urges-bharat-lal-nhrc-sg.html

By Kanu Sarda Updated: July 30, 2025 13:12 IST

The younger generation, which forms the backbone of India's future, must be equipped not only with academic knowledge but also with a strong moral compass rooted in India's cultural ethos, said Bharat Lal, Secretary General of the National Human Rights Commission (NHRC)

Speaking at THE WEEK Education Conclave 2025, he emphasised the urgent need to integrate ethics and values into the Indian education system, and added that empathy, compassion, and respect must be taught from an early age.

"All religions have taught us acceptance, and this is at the core of Indian values and ethos," Lal said. These values, he noted, are what make India unique as a civilisation. "The challenge today is to pass these values to the younger generation so that they evolve into responsible, ethical, and compassionate citizens."

He urged educational institutions to go beyond traditional academic goals and focus on holistic development. "Education should not only be for job creation but also for tackling life's challenges," Lal said. He suggested the introduction of a zero period in schools dedicated exclusively to inculcating values, life skills, and mental well-being.

"Mental health issues need to be addressed through our Indian value system," he added, pointing out that students must learn teamwork, cooperation, and self-reflection.

Lal underscored the importance of strong value systems in nurturing ethical leadership. "Leadership gives us strength, but ethical leadership must be the backbone if we are to excel as a society," he said. Citing the book Management by Values authored by IIM Kolkata, he recommended it as a must-read for students, as it emphasises management approaches anchored in ethics.

He also noted that many young people today are searching for deeper meaning in life beyond money or position. "They are looking for something else – a sense of purpose. This is what India has always given to those who seek it," Lal remarked.

He linked this quest for purpose to India's long tradition of yoga, meditation, and intellectual inquiry. By cultivating inner strength through such practices, students can better handle the pressures of modern life.

The NHRC secretary general also stressed the importance of teaching constitutional morality and fraternity as guiding principles. "We must instill respect, honesty, trust, and

justice in our students. These qualities will help them become good citizens and contribute to society in meaningful ways," he said. He further emphasised the need to include marginalised groups like transgender persons in mainstream life with dignity and equal opportunities.

Lal said he believes that life skills, anchored in values, are crucial to curbing the rising mental health challenges among youth. "It is the team effort and collective support that will truly help," he said, calling for educators and institutions to make values-based education a central priority.

He highlighted India's global reputation for producing citizens who are admired for their integrity and cultural grounding. "Our civilisation has evolved over millennia. It is our moral duty to transfer this legacy to the younger generation," Lal said.

By embedding ethics, values, and compassion into the curriculum, he said, India can create a generation capable of leading with empathy and purpose.

Dainik Bhaskar

डेगाना में डंपिंग यार्ड के लिए नहीं मिली स्थाई जगह: समाजसेवी ने मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई शिकायत, कलेक्टर को दिए समाधान के निर्देश

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/nagaur/degana/news/permanent-place-not-found-for-dumping-yard-in-degana-135563797.html

डेगाना10 घंटे पहले

डेगाना नगरपालिका क्षेत्र में कचरा निस्तारण के लिए स्थाई डंपिंग यार्ड न होने से आमजन परेशान हैं। इस समस्या को लेकर शहर के समाजसेवी एडवोकेट तेज सिंह रूवा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है।

एडवोकेट तेज सिंह ने बताया कि पहले कई बार नगरपालिका मंडल को इस समस्या से अवगत करवाया था। लेकिन कोई समाधान न होने पर उन्होंने आयोग में मुकदमा दर्ज करवाया। मानवाधिकार आयोग ने जिला कलेक्टर नागौर को इस समस्या का समाधान करने के आदेश दिए हैं।

नगरपालिका के गठन को 10 साल से अधिक समय हो चुका है। फिर भी कचरा निस्तारण के लिए स्थाई डंपिंग यार्ड अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। पहले कलेक्टर ने सूरियास गांव में जगह आवंटित की थी। लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था।

वर्तमान में नगरपालिका ने गौरेडी करणा बाईपास पर सरकारी खाली जगह पर अस्थाई डंपिंग यार्ड बना रखा है। ये स्थान शहर के आबादी क्षेत्र में है। इससे आसपास के निवासियों को बदबू और जलते कचरे के धुएं से परेशानी होती है।

इस अस्थाई डंपिंग यार्ड के आसपास गौरेडी करणा, राजकीय स्कूल, कस्तूरबा आवासीय स्कूल, सीबीईओ कार्यालय और कई कॉलोनियां हैं। यहां रहने वाले लोगों को गंदगी की बदबू और धुएं से सांस लेने में परेशानी होती है। इस स्थिति से आमजन में आक्रोश है।

शहर के कचरे, गंदगी और मृत पशुओं के अवशेषों के निस्तारण के लिए नगरपालिका के पास कोई स्थाई जगह न होने से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में समाजसेवी एडवोकेट तेज सिंह ने स्थाई डंपिंग यार्ड बनाने और शहर से दूर कचरा निस्तारण करने की मांग की है।

Zee News

Know Your Rights: क्रूरता, बदसलूकी या अमानवीय दंड के खिलाफ क्या है आपका ह्यूमन राइट्स, जानिए

Bihar Human Rights Commission: भारत एक लोकतंत्र देश है. यहां पर हर व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है. साथ ही मानवाधिकार संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है.

https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/patna/know-your-rights-what-are-your-human-rights-against-cruel-ill-treatment-or-inhuman-punishment/2861034

Reported By: Shailendra |Last Updated: Jul 30, 2025, 01:37 PM IST

Human Rights Protection: अगर किसी को भी यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड दिया जाता है, तो उसको ह्यूमन राइट्स के तहत सुरक्षा प्रदान किए गया है. पूरे भारत में मानवाधिकार संरक्षण का हक और अधिकार सभी लोगों के दिया गया है. वहीं, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी की गई है. इसकी स्थापना 3 जनवरी, 2000 की गई थी.

बिहार मानवाधिकार आयोग (BHRC) में लोक सेवकों की तरफ से मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत दर्ज करना होता है. इसका काम शिकायतों की जांच करना, जेलों और हिरासत केंद्रों का दौरा करना, कानूनों की समीक्षा करना और मानवाधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना है.

कैसे पहुंचे जानिए

आप पटना स्थित बीएचआरसी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसकी जानकारी अक्सर एनएचआरसी की वेबसाइट या बीएचआरसी के समर्पित पोर्टल पर मौजूद होते हैं. यहां जाने से पहले आप सभी दस्तावेज सही रखिए. सभी आवेदनों, शिकायतों, रसीदों की प्रतियां रखें.

प्राधिकरण को जानिए

आप सेवा या समस्या के लिए जिम्मेदार सही सरकारी विभाग या अधिकारी की पहचान करें. कभी-कभी, आपको अपने आवेदनों या शिकायतों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है. अगर आप अनिश्चित हैं, तो सलाह के लिए कानूनी सहायता प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों या किसी कानूनी पेशेवर से संपर्क करें.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना

मानवाधिकार आयोग नेटवर्क (HRCnet) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों दोनों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करता है.

Times of India

Sandhya Theatre stampede: Stopping Allu Arjun at `Pushpa 2' event couldve triggered chaos, police tell NHRC; say despite warnings actor conducted roadshow

https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/sandhya-theatre-stampede-stopping-allu-arjun-at-pushpa-2-event-couldve-triggered-chaos-police-tell-nhrc-say-despite-warnings-actor-conducted-roadshow/articleshow/122994449.cms

TNN | Jul 30, 2025, 02.50 PM IST

HYDERABAD: Nearly six months after a deadly stampede at Sandhya theatre claimed the life of a woman during the premiere of Pushpa 2: The Rule, Hyderabad police have told the National Human Rights Commission (NHRC) that they did not stop actor Allu Arjun and the film's crew from entering the venue-despite not granting permission-because doing so could have triggered mass public disorder.

The justification was made in a written report by assistant commissioner of police (Chikkadpally division) L Ramesh, submitted last month and reviewed by the NHRC on Monday. The commission is currently hearing a plea filed by high court advocate Rama Rao Immaneni, who alleged police negligence in the stampede incident that killed Revathi and seriously injured her son Sri Tej.
Police have not initiated legal action against the actor/management prior to the incident due to large gathering of fans at event," the ACP said. "Any attempt to take action would have risked escalating crowd into a mob, potentially leading to damage of public property and further breach of public order," he said.

The NHRC earlier raised pointed questions after an initial report submitted by Hyderabad police in April. Among them: Why was the actor or the film's management allowed to gather despite having no permission? Why wasn't action taken beforehand to prevent the unlawful gathering?
In a follow-up report filed in June, the ACP replied: "It is to submit that, practically, it is not possible to take legal action against accused actor/management at the very first occurrence as there is a crowd surge, and the priority for the police was to control the crowd and prevent loss of life or damage to the property."

The NHRC had sought to know whether police foresaw the risk of injury or disorder when denying permission, and whether they warned the public, the management, and the actor in advance.

Police responded that the permission was denied based on a clear risk assessment, citing public safety and crowd control concerns. They again blamed Allu Arjun and his team for triggering the chaos. "The actor, after reaching theatre, conducted a roadshow by standing on his car's sunroof and waving to the public, prompting the crowd to surge towards his vehicle," police said.

"This was done despite several warnings given by the cops. Despite knowing about incident, the actor, while retreating, again appeared through the sunroof making gestures. He was immediately asked by the cops to get back inside the vehicle," police said. However, no chargesheet has yet been filed by the Chikkadpally police.

Advocate Rama Rao said, "The commission found that the investigation officer has not furnished details about the progress made in probe. So, the IO has to file another report and commission will take up this case after two weeks." Though 10 persons, including Allu Arjun, were arrested, further legal action is awaited.

The News Minutes

Pushpa 2 stampede: Cops say they didn't stop Allu Arjun's theatre visit due to crowd

The National Human Rights Commission had asked the Hyderabad police why they didn't stop Allu Arjun's unauthorised visit to Sandhya theatre, which led to the stampede that killed a woman and critically injured her son.

https://www.thenewsminute.com/telangana/pushpa-2-stampede-cops-say-they-didnt-stop-allu-arjuns-theatre-visit-due-to-crowd

Written by: TNM Staff | Published on: 30 Jul 2025, 2:04 pm

In the ongoing investigation of the December 2024 theatre stampede involving actor Allu Arjun, the Chikkadpally Assistant Commissioner of Police has justified not taking action against the movie star before the stampede.

The stampede, which took place on December 4, 2024, was triggered by Allu Arjun's sudden visit to the Sandhya theatre at RTC crossroads for a premiere show of his film Pushpa 2: The Rule. A woman named Revathi died in the stampede.

ACP L Ramesh informed the Hyderabad Commissioner of Police that trying to take action against Allu Arjun before the stampede occurred "would have risked escalating the crowd into a mob, potentially leading to damage to public property and further breach of public order."

Since the police had denied permission to Allu Arjun's team and the Sandhya 70 mm theatre management for the actor's visit on December 4, the National Human Rights Commission (NHRC) had questioned why the police allowed the crowd and Allu Arjun to gather for an event which did not have permission.

"The police should have taken legal action against accused actor/management at the very first occurrence, prior to incident itself, for breaking the law and attending the unlawful events," the NHRC said, according to the ACP's letter.

In his letter to the Hyderabad Commissioner of Police, the ACP on July 19 said that they had denied permission for Allu Arjun's visit to Sandhya theatre in RTC crossroads anticipating large crowds. The official letter declining the permission for the visit was attached as proof.

The ACP said that trying to take action on Allu Arjun after he appeared at RTC crossroads would have made it very difficult to control the crowd, as people had already gathered in huge numbers.

"Any attempt to take action would have risked escalating the crowd into a mob, potentially leading to damage to public property and further breach of public order… practically it is not possible to take legal action against the accused actor/management at the very first occurrence as… [it] was in concurrence of the crowd surge… the priority…at the

moment…was to control the crowd and prevent loss of life or damage to the property," the ACP wrote.
The area being densely crowded even at other times made it difficult for the police to identify and prevent fans from gathering at the theatre, the ACP said.

"The Chikkadpally area is densely populated with students, study circles, and various restaurants like Bawarchi, Astoria and Crystal, making it challenging for the police to sift the public who are coming to watch the movie at that point in time," he said.

He said that the police had arranged bandobast at the theatre premises as a precautionary measure.

The tragic stampede occurred on December 4, 2024, when hundreds of fans gathered at Sandhya theatre to catch a glimpse of the actor. Allu Arjun, who arrived near the theatre at around 9.35 pm, waved at the crowd through the sunroof of his car, escalating the frenzy.

As the actor entered the theatre, a huge crowd followed him. In the chaos, the gate of a lower balcony collapsed and caused a stampede, leading to the death of 35-year-old Revathi. Her eight-year-old son, Sri Teja, was hospitalised on respiratory support for five months before being discharged for neurorehabilitation.

Allu Arjun's road show caused frenzy

The NHRC also asked whether the police had warned the crowd, the theatre management and Allu Arjun against the gathering, as they had clearly foreseen the potential tragedy which is why they had denied permission for the visit.

To this, the ACP claimed that the incident was unforeseeable as Allu Arjun had conducted a roadshow and waved from his car's sunroof, causing a further surge of crowd towards his vehicle and the theatre. "This was done despite several warnings given by the police to the actor, actor's manager and the theatre management," the ACP said.

Even after the actor was escorted out of the theatre following the stampede, despite having knowledge of the incident, Allu Arjun again waved through the sunroof, the ACP wrote in the letter. The Chikkadpally police justified their management of the incident, stating that they prioritised public safety and acted with due diligence under "challenging circumstances" to control the situation and prevent further harm.

They said that it was Allu Arjun's "overt act" which caused the crowd to swell and caused the stampede. Taking immediate action against the actor was not feasible at that time without risking public safety, they said.

"However, immediately after the incident a case was registered under sections 105 (culpable homicide), 118(1) (voluntarily causing hurt) read with 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) against the actor, his bouncers and management of the theatre and all other concerned," the letter read.